दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, सोमवार 12 जुलाई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 282

सख्ती के बाद ढीले पड़े ट्विटर के तेवरः नए नियम के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति

» दो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का भी दिया संकेत

» कार्रवाई संबंधी मासिक रिपोर्ट भी की पेश

» कानूनी सुरक्षा बहाल करने पर जल्दबाजी नहीं दिखाएगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार की सख्ती के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त तेवरों के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर धीरे-धीरे नरम रुख अख्तियार करने पर मजबूर होता दिख रहा है। रविवार को ट्विटर ने रेजिटेंड ग्रीवेंस ऑफिसर (शिकायत निवारण अधिकारी) के रूप में विनय प्रकाश की नियुक्ति की है। इसके अलावा कंपनी ने शिकायतों के संदर्भ में की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट भी पेश की है। उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी देश के नए नियमों के मुताबिक जल्द ही दो अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा।

गौरतलब है कि रविशंकर प्रसाद की जगह आए नए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो टूक शब्दों में कहा था कि देश में कानून और संविधान के ऊपर कोई नहीं है। ट्विटर को देश के नियम और संविधान का पालन करना ही होगी। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नए नियमों के संदर्भ में ट्विटर को राहत देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बीच ट्विटर ने सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने की बात कही थी।

❒ **सरकार को भावी रुख का इंतजार-** नए नियम के मुताबिक 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली कंपनियों को हर हाल में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। हथियार डालने का संकेत देते हुए ट्विटर ने फिलहाल शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है। उसे जल्द ही दो अन्य नियुक्तियां करनी है। सरकार को अब कंपनी के भावी रुख का इंतजार है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में ट्विटर के साथ नरमी नहीं बरतेगी। गौरतलब है कि नए नियमों के मुताबिक तीनों अधिकारियों का भारतीय नागरिक होना भी अनिवार्य है।

❒ **क्या है मासिक रिपोर्ट में-** शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के साथ ट्विटर ने शिकायतों के निपटारे से संबंधित मासिक रिपोर्ट भी रखी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने या ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी 5464 शिकायतें मिली। इसके अलावा 5412 अन्य मामलों में कानूनी अनुरोध किया गया है। शिकायतों के संदर्भ में अब तक 248 ट्विटर हैंडल को बंद किया गया है। इसके अलावा 2759 ट्वीट्स को फिलहाल रोका गया है। इस क्रम में 3649 मामलों में ट्विटर हैंडल को निलंबित या विवादास्पद ट्वीट को हटाया गया है।

❒ **नियम के पूर्ण पालन केबाद ही राहत-** सरकार ने फिलहाल ट्विटर को मिली कानूनी सुरक्षा को खत्म कर दिया है। कानूनी सुरक्षा खत्म होने के बाद ट्विटर के खिलाफ हर्जाना, मानहानि और आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि ट्विटर जब तक नए नियमों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे पहले मिली हुई कानूनी सुरक्षा बहाल नहीं होगी।

प्रधानमंत्री ने लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित करने के लिए किया आमंत्रित

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार ने जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित करने के लिए आमंत्रित किया। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं- पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए), पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा) और पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा) के लिए।

पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है। यहां तक कि स्व-नामांकन भी किया जा सकता है।

पुरस्कार के लिए नामांकन करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा, भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर, हम उनमें से बहुत कुछ नहीं देखते या सुनते हैं। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हे हैशटैग पीपुल्स पद्म के लिए नामांकित कर सकते हैं। इसके लिए नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले महीने पद्म पुरस्कार 2022 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू किया था। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 है। पुरस्कारों की घोषणा 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी।

केंद्र सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार-भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की। बाद वाले में तीन वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग।

महत्वपूर्ण एवं खास

कुंए में दम घुटने से पिता-पुत्र की मौत

सिवनी (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड के उगली थाना क्षेत्र के कातोली गांव में स्थित एक कुएं में दम घुटने से आज एक पिता-पुत्र की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायत कातोली का निवासी दुर्गाप्रसाद चौहान अपने पुत्र रंजीत चौहान के साथ खेत में धान का रोपा लगाने आज सुबह खेत पर गया था। तभी खेत में स्थित कुएं में लगा मोटर पंप खराब हो गया, जिसे देखने दुर्गाप्रसाद कुएं में उतरा और बेहोश होकर कुंए के पानी में गिर गया। पिता के कुएं के पानी में गिरने की आवाज सुनकर रंजीत चौहान भी कुएं में उतर गया और कुंए में उसकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को मौके पर मौजूद आसपास के ग्रामीणों ने दी। इसके बाद पुलिस बल ने मौके पर दोनों के शव स्थानीय ग्रामीण की सहायता से कुंए से बाहर निकाले।

करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत, एक दूसरे को बचाने में गई जान

नई दिल्ली (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के छतरपुर में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा बिजावर इलाके के महुआ झाला गांव में हुआ। बिजावर पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि महुआ झाला गांव में एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था और उसके ऊपर छत (लेंटर) डाल दी गई थी। उन्होंने बताया कि आज सुबह इस छत पर लगी सेंटिंग को हटाने के लिए एक व्यक्ति सेप्टिक टैंक में उतरा और टैंक में रोशनी के लिए लगाई गई लाइट से अचानक करंट फैल गया और वह उसकी चपेट में आ गया। ठाकुर ने बताया कि इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके परिवार के पांच अन्य लोग भी एक-एक कर सेप्टिक टैंक में उतरते गए और वे भी करंट की चपेट में आते गए, जिससे छह लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा- छतरपुर के थाना बिजावर, महुआ झाला गांव में शौचालय निर्माण के लिए मिट्टी खोदने के दौरान अहिरवार समुदाय के 6 लोगों की करंट लगने से निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों की पहचान लक्ष्मण अहिरवार (65), शंकर अहिरवार (35), उसके दो भाई राम प्रसाद (32) एवं मिलन अहिरवार (28), नरेंद्र अहिरवार (25) एवं उसका भाई विजय अहिरवार (20) के तौर पर हुई है।

पोल से टकराकर कार में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले

गुरुग्राम (आरएनएस)। गुरुग्राम में मारुति ईको वैन के बिजली के खंभे से टकराने और उसमें आग लगने से दो लोग अपनी सीट से बंधे हुए जिंदा जल गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना शाम करीब पांच बजे की है। पुलिस ने कहा कि टिकली-गैरतपुर बास गांव रोड पर वैन एक पोल से टकरा गई, पलट गई और उसमें आग लग गई और हरियाणा के मेवात जिले के निवासी सनी और खन्ना कार में फंस गए और उनकी जलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, दोनों गैरतपुर बास गांव से बादशाहपुर लौट रहे थे।

गडकरी ने नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का किया उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने आज नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में पेट्रोल-डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 8 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। मंत्री ने कहा कि हमने एक नीति तैयार की है जो आयात के विकल्प को लागत प्रभावी प्रदूषण मुक्त व स्वदेशी इथेनॉल, जैव सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन ईंधन के विकास को प्रोत्साहित करती है। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों पर लगातार काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमें चावल, मक्का और चीनी को बर्बाद होने से बचाने के लिए अधिशेष का उपयोग करना होगा।

फ्लेक्स इंजन के बारे में गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं विशेषकर चौपहिया और दुपहिया वाहनों के लिए फ्लेक्स इंजन बनाना अनिवार्य करने के संबंध में तीन महीने में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका, कनाडा और ब्राजील जैसे कई देशों के पास फ्लेक्स इंजन पहले से ही हैं। उन्होंने कहा कि वाहन की कीमत एकसमान रहती है, चाहे वह पेट्रोल हो या फ्लेक्स इंजन।

पुरी में रथ यात्रा को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

भुवनेश्वर (आरएनएस)। पुरी में 12 जुलाई को होने वाली वार्षिक रथयात्रा के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा सरकार ने त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 65 प्लाटून बल तैनात किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक (कानून व्यवस्था) आर.के. शर्मा ने कहा, पूरे शहर को 12 जोन में बांटा गया है। पुरी में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि 65 प्लाटून के साथ अतिरिक्त एसपी रैंक के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को उत्सव के लिए तैनात किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि पुलिस बल न केवल सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे कोविड-19 दिशानिर्देशों का उचित प्रवर्तन भी सुनिश्चित करेगा। एक सूत्र ने कहा कि रथयात्रा उत्सव के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों और अन्य जगहों से पुरी तक लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए जिले के सभी प्रवेश बिंदुओं (8 चेक प्वाइंट) को सील कर दिया जाएगा।

पिछले साल की तरह, पुरी के तीर्थ शहर में भगवान जगन्नाथ का पूजन उत्सव कोविड-19 स्थिति को देखते हुए भक्तों की भागीदारी के बिना आयोजित किया जाएगा। सेवादारों का आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जा रहा है। कोविड-19 टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट वाले सेवायत (सेवक) और जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हें रथ खींचने में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच ग्रांड रोड स्थित सभी होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों को किसी भी पर्यटक या श्रद्धालु को अनुमति नहीं देने को कहा गया है। उन्हें शनिवार शाम तक सभी बोर्डर और मेहमानों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने भी शनिवार को बंद में ढील दी है। हालांकि रविवार रात 8 बजे से सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी और ग्रैंड रोड पर किसी भी दुकान या आवश्यक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

आधी रात कांधार से सुरक्षित लाए गए राजनयिक- अधिकारी

» ऑपरेशन के लिए वायु सेना के विशेष विमान का हुआ इस्तेमाल

» अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास-मिशन केंद्र अस्थाई रूप से बंद

» तालिबान के बढ़ते प्रभाव के कारण खतरे में थे राजनयिक और अधिकारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने बीती देर रात कांधार स्थित वाणिज्य दूतावास से जुड़े करीब 50 राजनयिकों, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वायुसेना के विशेष विमान के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वाणिज्य दूतावास में अब भी सीमित संख्या में कर्मचारी मौजूद हैं। इनकी स्वदेश वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य दूतावास और मिशन केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।

दरअसल अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। खासतौर से दक्षिण अफगानिस्तान में पाकिस्तान स्थिति आतंकी संगठन लश्कर ए तयबा तालिबान लड़ाकों के साथ मिल गए हैं। इन्होंने दक्षिण अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बढ़ते संकट के बीच भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान को सुरक्षा के लिए कॉल करना पड़ा।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि शनिवार देर रात राजनयिकों, कर्मचारियों और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के जवानों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना के विशेष विमान की मदद ली गई। विशेष विमान देर रात कांधार पहुंचा और करीब 50 लोगों के साथ वापस लौटा। फिलहाल दूतावास में अभी कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। इन्हें भी जल्द बाहर निकालने की योजना बनाई जा रही है।

अचानक बिगड़े हालात

नाटो सैनिकों की विदाई के बावजूद भारत ने काबुल में मिशन केंद्र और कांधार के मजार ए शरीफ शहर में वाणिज्य दूतावास को बनाए रखने की घोषणा की थी। भारत ने कहा था कि उसका मिशन केंद्र और वाणिज्य दूतावास को बंद करने की कोई योजना नहीं है। इस बीच अचानक हालात बद से बदतर होने और तालिबान लड़ाकों के कई इलाकों पर कब्जा करने के बाद भारत ने आपात योजना के जरिए अपने राजनयिकों, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई।

भारत एक मित्र देश होने के नाते अफगानिस्तान में शांति, सद्भाव और संप्रभुता की बहाली के लिए प्रयासरत रहेगा। हम अफगानिस्तान की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल ने मंत्रालय की वर्तमान में जारी परियोजनाओं की समीक्षा की

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल ने आज मंत्रालय की वर्तमान में जारी सभी चालू परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन ने मंत्री महोदय को मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। मंत्री ने अपने कक्ष में मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की। सर्बानंद ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों के सभी अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नई टीम के साथ गंभीर प्रयास करेंगे कि सभी निर्धारित लक्ष्य बिना किसी देरी के हासिल किए जाएं।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन, अपर सचिव, संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव (पत्तन) विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव (प्रशासन) लुकास एल कामसुआन, ने परिवहन भवन, नई दिल्ली स्थित पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में पहुंचने पर केन्द्रीय मंत्री का स्वागत किया।

बारां में धारा 144 लागू, एक दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान के बारां शहर में एक किशोर की हत्या के बाद एहतियात के तौर पर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई जबकि एक दिन के लिए बारां नगर परिषद क्षेत्र में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार शाम को हुई इस किशोर की हत्या के बाद पोस्टमार्टम के दौरान रात को मृतक के परिजन एव अन्य लोग मोर्चरी के सामने ही धरने पर बैठ गए थे। मध्य रात्रि के बाद पुलिस एवं प्रशासनिनक अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर शव का अंतिम संस्कार के लिए राजी किया गया।

इसके बाद आज सुबह ऐहतियात के तौर पर शहर में धारा 144 लागू कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके अलावा शहर में 12 जुलाई तडके तीन बजे तक अस्थाई रुप से इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। हालांकि शांति बनी हुई हैं कहीं से कोई गड़बड़ की सूचना नहीं हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही हैं और जल्द ही हत्या का खुलासा होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि कृषि उपज मंडी के सामने श्रमिक कालोनी निवासी आजाद की शनिवार शाम अनाचक गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।

91 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा वाली 23 फर्मों के नेटवर्क का किया खुलासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, दिल्ली (पश्चिम) की चोरी-रोधी शाखा के अधिकारियों ने लगभग 91 करोड़ रुपये के माल रहित चालान के माध्यम से अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ/उपयोग और पारित करने के फर्जी मामले का पता लगाया है। इस मामले में अस्वीकार्य क्रेडिट का लाभ उठाने/इनका उपयोग करने और पारित करने की कार्य-प्रणाली में कई फर्मे शामिल थीं।

इस नेटवर्क में शामिल फर्मों में मेसर्स गिरधर एंटरप्राइजेज, मेसर्स अरुण सेल्स, मेसर्स अक्षय ट्रेडर्स, मेसर्स पद्मावती एंटरप्राइजेज और 19 अन्य शामिल हैं। ये 23 फर्मे सरकार को वास्तविक जीएसटी का भुगतान किए बिना धोखाधड़ी वाले आईटीसी को पारित करने के इरादे से माल-रहित चालान बनाने में शामिल थीं। स्वर्गीय दिनेश गुप्ता, शुभम गुप्ता, विनोद जैन और योगेश गोयल फर्जी चालान बनाने/बेचने के उक्त व्यवसाय से जुड़े थे। ये संस्थाएं विभिन्न वस्तुओं का कारोबार कर रही हैं और 551 करोड़ रुपये के माल-रहित चालान बनाने और 91 करोड़ (लगभग) रूपए की अस्वीकार्य आईटीसी पास करने में शामिल हैं। तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से बयान दिया है।

इसलिए शुभम गुप्ता, विनोद जैन एवं योगेश गोयल ने जानबूझकर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(बी) एवं 132(1)(सी) के तहत अपराध किया जो कि संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध हैं और धारा 132(5) के प्रावधान और उक्त अधिनियम की धारा 132 की उप धारा (1) के खंड (ख) के तहत दंडनीय हैं। तदनुसार, उन्हें 10.07.2021 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

दिल्ली जोन जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, वर्तमान वित्त वर्ष में 91.256 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया है। और इन मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।